संख्या-100 /2023/2221 /30-3-2023

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 02 अगस्त, 2023

विषय- इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी वितरण हेतु 02 माह की आवश्यकतानुसार धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-182(शा0)सा0प्र0/2023-08टीआर/2016-22, दिनांक 14 जुलाई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु (03 व्हीलर वाहनों को छोड़कर) 31 अगस्त, 2023 तक 02 माह हेतु आवश्यक धनराशि रू0 60.49 करोड़ (रूपये साठ करोड़ उनचास लाख मात्र) को भारतीय स्टेट बैंक में खोले जाने वाले खाते में हस्तांतरित करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु (03 व्हीलर वाहनों को छोड़कर) 31 अगस्त, 2023 तक 02 माह हेतु आवश्यक धनराशि रू0 60.49 करोड़ (रूपये साठ करोड़ उनचास लाख मात्र) को भारतीय स्टेट बैंक में खोले जाने वाले खाते में हस्तांतरित करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-06-इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी-27-सब्सिडी की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-128-X-2023-24, दिनांक 31 जुलाई, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-100/2023/2221(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।